whiich trade data is available, is given below: —

Rupee Terms

(Rs. Crores)

Year	Exports		
	RPA	GCA	TOTAL
1991-92	4433	39609	44042
1992-93 (April-December)	1357	35972	37329

Dollar Terms

(US Million)

Year	Exports		
	RPA	GCA	TOTAL
1991-92	1798	16067	17865
1992-93 (April-December)	475	12600	13075

कोयले के मूल्यों में वृद्धि से कोयला उत्पादन राज्यों पर पड़ने वाला प्रभाव

***274. श्री सत्य प्रकाश मालवीय :**
श्री अनन्तराम जायसवाल :

क्या कोयला मंत्री 1 मार्च, 1993 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न सं. 698 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला के मूल्यों में की गई वृद्धि से कोयला उत्पादक राज्यों को लाभ होने की संभावना है और क्या सरकार वहां पर कोयले की बिक्री दर में कोई छूट देने का विचार रखती है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ;

(ग) कोयले का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है और वहां किस किस्म के कोयले का उत्पादन किया जाता है ; और

(घ) पिछले तीन वर्षों में सरकार को वर्ष-वार तथा राज्य-वार कुल कितना कोयला प्राप्त हुआ है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) और (ख) ऐसी राज्य सरकारें, जहां के कोयला उत्पादित किया जाता है, उनके द्वारा कोयले पर लगाए गए उपकरन लगाए गए यथा-मूल्य कर से प्राप्त अतिरिक्त राजस्व के जरिए उन्हें कोयले की कीमतों में हुई वृद्धि से लाभ मिलेगा अर्थात् पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा लगाए गए यथामूल्य उपकर और ऐसे अन्य राज्यों द्वारा लगाए गए बिक्री कर के मामले में भारत सरकार

द्वारा कोयले की कीमतों तथा सभी अन्य कर पिटहैड आधार पर निर्धारित किए जाते हैं, अर्थात् रायल्टी, उपकर, बिक्री कर, आदि जिनकी अदायगी पिटहैट कीमत के ऊपर उपभोक्ता द्वारा की जाती है । भारत सरकार द्वारा निर्धारित कोयले की पिटहैड कीमतों में किसी तरह की छूट देने की कोई व्यवस्था नहीं है ।

(ग) वर्ष 1991–92 के कोयले के उत्पादन के उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर मध्य प्रदेश कोयले का अधिकतम उत्पादन करने वाला राज्य है । इस राज्य में उत्पादित कोयले की किस्म कोककर कोयले में वाशरी ग्रेड-II से लेकर अकोककर कोयले के ग्रेड "ए", "बी", "सी", "डी", "ई" तथा "एफ" ग्रेड तक उत्पादित किया जाता है ।

(घ) अद्यतन उपलब्ध सूचना के अनुसार कोल इंडिया लि. द्वारा पिछले 3 वर्षों के दौरान कोयले के राज्य-वार किए गए प्रेषण को नीचे दर्शाया गया है ।

(000 टन में)

राज्य का नाम/संघ शासित क्षेत्र का नाम	कुल प्रेषण		
	1989–90	1990–91	1991–92
1	2	3	4
1. बिहार	17,850	17,512	17,387
2. पश्चिम बंगाल	14,559	15,805	18,872
3. उत्तर प्रदेश	27,644	27,641	30,475
4. उड़ीसा	8,790	8,613	9,422
5. मध्य प्रदेश	29,545	31,618	33,217
6. महाराष्ट्र	19,156	20,838	23,793
7. गुजरात	13,663	14,655	15,181
8. राजस्थान	3,909	3,914	5,206
9. दिल्ली	4,420	5,025	5,542
10. पंजाब	5,801	5,996	0,210
11. हरियाणा	3,523	2,976	3,860
12. तमिलनाडु	7,259	7,987	8,730

1	2		4
13. आंध्र प्रदेश . . .	2,751	3,547	4,445
14. कर्नाटक	1,179	2,049	2,329
15. केरल	159	174	230
16. जम्मू एवं कश्मीर . . .	300	302	257
17. हिमाचल प्रदेश . . .	135	220	190
18. असाम	744	816	830
19. अन्य	409	273	540

*कोल इंडिया लिमिटेड (कोल इं० लि.)

Withdrawal of international price Reimbursement scheme

@)*275. SHRI ANANT RAM JAISWAL:

SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA:

Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether Government propose to withdraw the International Price Reimbursement Scheme in respect of the small scale industry; and

(b) if so, what is the decision, if any, taken by Government in this regard, stating the overall impact of the withdrawal of the scheme on the small scale industry?

THE MINISTER OF COMMERCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE): (a) and (b) No decission has been taken by the Government to withdraw the International Price Reimbursement Scheme (IPRS) whether for the small scale or any other sector of the engineering goods industry. The Ministry of Steel is advocating the abolition of the cess which is now financing the IPRS. At the same time, the exists cell being collected is not sufficient to meet the claims under the IPRS. Government is yet to take a final view on the future shape of the IPRS.

@ Previously Starred Question 55, transferred from 25.2.1993.

Money blocked by Iraqi Banks

*276. SHRI B. K. HARIPRASAD: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state;

(a) whether lit is a fact that more than Rs. 1,000 crores have been blocked by Iraqi banks causing hardship to Indians, including overseas Indian contractors engaged in Iraqi projects;

(b) whether Government have made any diplomatice move to get the funds released at the earliest; and

(e) if so, the details thereof?